(b) if so, the reasons for going against the wishes of the World Bank and its reaction thereon;

(c) whether Government propose to invite fresh bids for Phase-II of that project to bring down its cost; and

(d) if so, the stage of considera tion of the entire project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is for Government of Maha rashtra to take a suitable decision in this matter.

(d) Does not arise.

बिहार में विद्युत संकट

7875. **श्री आस मोहम्मद : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विद्युत संकट बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार में ऊर्जा की आवश्यकता 9410 मिलियन यूनिट थी, जबकि इसकी तुलना में उपलब्धता 6295 मिलियन यूनिट थी, जो उसी अवधि के दौरान 7.1 की अखिल भारतीय औसत कमी की तुलना में 33.1% की कमी को द्योतक है ।

(ख) बिहार विद्युत की उपलब्धता की तुलना में विद्युत की मांग अधिक होने के कारण विद्युत की कमी का सामना कर रहा है ।

(ग) मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्प अवधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, विद्यमान विद्युत स्टेशनों के कार्य निष्पादन में सुधार करना पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन पायों को क्रियान्वित करना और पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से ऊर्जा के अंतरण क व्यवस्था करना आठवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में 476.5 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है । इसके अलावा, पूर्वी क्षेत्र में अधिष्ठापित किए जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से भी राज्य अपने समुचित हिस्से की विद्युत प्राप्त करेगा ।

गुजरात में गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों का प्रस्ताव

7876. **श्री संघ प्रिय गौतम : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में गैरसरकारी क्षेत्र से गैस आधारित, लिग्नाइट और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के संबंध में वर्षवार कितने प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उस राज्य में किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी क्षमता का संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और उनमें अन्तर्ग्रस्त गैरसरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन आवेदनों/प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(घ) प्रत्येक संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है और क्या इन गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों ने प्रस्तावित

परियोजनाओं के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली है ;

(ङ) राज्य सरकार ने इस बारे में क्या रवैया अपनाया है ; और

(च) क्या सरकार राज्य सरकार की सहायता से इन गैर-सरकारी कम्पनियों के लिए विद्युत बाण्ड्स जारी करने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्र

7877. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इन संयंत्रों की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) उस राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्रीय में विद्युत संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों को औसतन कितने समय में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार का 4872 मे०वा० की क्षमता अभिवृद्धि हेतु निजी क्षेत्र में 18 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) भारत सरकार परियोजनाओं के लिए अपेक्षित स्वीकृतियों में तेजी प्रदान करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, राज्य सरकार के प्रवर्तकों को सहायता प्रदान कर रही है। जैसे ही आवश्यक निवेशों स्वीकृतियों के संबंध में प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाता है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि०प्रा०) इन्हें अपनी तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करता है ।

बिजली की बरबादी को रोकना

7878. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोई ऐसी तकनीक अपनाने का सुझाव दिया है जिसके प्रयोग से बड़े पैमाने पर बिजली की बरबादी को रोका जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) उक्त तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) विद्युत उत्पादन को कम खर्चीला बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा सके ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "शहरी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन संयंत्रों और आटोमोबाइल्स में प्रदूषण नियंत्रण हेतु पूर्व-अपेक्षाएं" शीर्षक से एक पत्र परिपत्रित